

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
09.02.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1359 का उत्तर

नई रेल लाइन परियोजना का सर्वेक्षण

1359. श्री प्रिंस राज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा कर्पूरीग्राम-ताजपुर-महुआ भगवानपुर की नई रेल लाइन परियोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में प्रावधान करने की संभावना है;
- (ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या उक्त लाइन के चालू होने के बाद समस्तीपुर और वैशाली जिलों के लाखों लोगों की यात्रा आसानी से होने की संभावना है;
- (ङ.) क्या उक्त परियोजना से मिथिलांचल सहित पटना और समस्तीपुर के बीच की दूरी कम से कम 100 किमी कम होने की संभावना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

नई रेल लाइन परियोजना का सर्वेक्षण के संबंध में 09.02.2022 को लोक सभा में श्री प्रिंस राज के अतारांकित प्रश्न सं. 1359 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) से (च): भगवानपुर स्टेशन हाजीपुर-मुजफ्फरपुर दोहरी लाइन खंड पर विद्यमान है और कर्पूरीग्राम स्टेशन समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर दोहरी लाइन खंड पर विद्यमान है। भगवानपुर और कर्पूरीग्राम स्टेशन मुजफ्फरपुर के रास्ते रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

महुआ के रास्ते भगवानपुर से कर्पूरीग्राम के लिए सर्वेक्षण कार्य 2020-21 में पूरा कर लिया गया है। परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इसे वित्तीय रूप से अर्थक्षम नहीं पाया गया है, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

हाजीपुर-मुज्जफरपुर का दोहरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। क्षेत्र में मुज्जफरपुर-सुगौली दोहरीकरण और हाजीपुर-वैशाली-सगौली नई लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं से समस्तीपुर और वैशाली जिले के लोगों की यात्रा और आसान हो जाएगी।

वर्ष 2014 से रेल बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसके अनुरूप पूरा कर लिया गया है। 2014-19 के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान, 1,132 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3,061 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 170% अधिक है। यह आबंटन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 4,093 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 262% अधिक) और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4,489 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 297% अधिक) बढ़ाया गया है। इन परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 5,560 करोड़ रुपये (मूल बजट परिव्यय (ब.अ.) 5,150 करोड़ रुपये और अतिरिक्त आबंटन 410 करोड़ रुपये) अब तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय मुहैया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय (1,132 करोड़ प्रति वर्ष) की तुलना में 391% अधिक है।

2014-21 के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 968 किमी लंबाई (317 किमी नई लाइनें, 345 किमी आमान परिवर्तन और 306 किमी दोहरीकरण) को 138.29 किमी. प्रतिवर्ष की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है, जो 2009-14 के दौरान (63.6 किमी./प्रतिवर्ष) यातायात के लिए चालू किए गए किमी. से 117% अधिक है।
